

**शहर: लुधियाना**

**राज्य: पंजाब**

**श्रेणी: व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्र, टायर 2**

लुधियाना शहर पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में निहित है और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। आधिकारिक सूत्रों का सुझाव है कि शहर 159.37 वर्ग किलोमीटर में फैला है एवं लगभग 1.6 लाख लोगों की आबादी है। उत्तर भारतीय शहर जो सतलुज नदी के किनारे बसा है एवं एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय का मेजबान है। यह शहर उत्तर भारत में एक अच्छी तरह से विकसित विनिर्माण एवं व्यावसायिक केन्द्र के साथ साथ सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है।

### 1. जनसांख्यिकी प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
कुल जनसंख्या	1618879	10399146	377,106,125
यूए की कुल जनसंख्या (यदि)			
जिला शहरी आबादी में यूएलबी आबादी की हिस्सेदारी (%)	78.22		
जनसंख्या वृद्धि दर (एईजीआर) 2001-11	1.46	2.30	2.76
क्षेत्र (वर्ग मीटर)*	159.37		
जिले में यूएलबी क्षेत्र का हिस्सा (%)*#	4.24		
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति वर्ग प्रति किमी)*	10158		
साक्षरता दर (%)	85.77	83.18	84.11
अनुसूचित जाति (%)	14.32	22.72	12.60
अनुसूचित जनजाति (%)	0	0	2.77
युवा, 15-24 वर्ष (%)	19.81	19.93	19.68

स्लम जनसंख्या (%)	15.08	22.58	17.36
कार्य आयु समूह, 15-59 वर्ष (%)	66.82	66.56	65.27

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

\*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

#एक से अधिक जिले में फैले हुए शहरी स्थानीय निकाय

## 2. आर्थिक प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
2004-05 के स्थायी कीमत पर प्रति व्यक्ति आय (₹.)*	51633	42868	₹. 35,947 <sup>a</sup>
शहरी गरीबी का अनुपात (शहरी आबादी का %)**	9.51	9.2	13.7
बेरोजगारी दर, 2011-12***	0	2.8	3.4
कार्य करने वालों की दर, 2011-12***	38.26	36.8	35.5
कार्य की स्थिति, 2011-12 (प्रतिशत)***			
स्व नियोजित:	33.74	44.5	42.0
नियमित/मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारी:	63.6	47.8	43.4
अनौपचारिक श्रम।	2.66	7.6	14.6
मजदूरों का क्षेत्रवार वितरण, 2011-12 (प्रतिशत)***			
प्राथमिक	0.85	5.7	7.5
द्वितीय	51.49	37.4	34.2
तृतीयक	47.66	56.9	58.3
प्रमुख व्यवसायों द्वारा मजदूरों का वर्गीकरण, 2011-12 (प्रतिशत)***			
व्यवस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	8.22	16.4	15.8
व्यवसाय	4.80	7.9	8.8
तकनीशियनों और एसोसिएट पेशेवर	9.14	7.1	6.7
	1.19	4.4	5.0

क्लर्क	14.55	14.0	14.7
सेवा श्रमिक और दुकान एवं मार्केट सेल्स श्रमिक	0.81	5.4	4.6
कुशल कृषि एवं मत्स्य श्रमिक	20.31	18.3	19.2
शिल्प और संबंधित ट्रेडों के श्रमिक	18.49	10.0	9.2
प्लांट और मशीन ऑपरेटरों और संयोजनकर्ता (अस्सेम्ब्लेर्स)	22.47	16.6	16.1
एलिमेंटरी व्यवसाय श्रमिक कब्जे से वर्गीकृत नहीं	0	0	0.1
प्राथमिक वस्तु निर्माता#	होजरी और वस्त्र सामान, साइकिल और साइकिल पाटर्स, मशीनरी और ऑटो पाटर्स		
प्रमुख उद्योग##	ऑटोमोबाइल, बाइसाइकिल और पाटर्स, एल्यूमीनियम और पीतल, तांबा, लोहा और स्टील के अन्य उत्पाद। वस्त्र और साइकिल पाटर्स		
अनुमोदित एसईजेड की संख्या	0	4	413

नोट: 2009-10, 2010-11, 2011-12 का 3 वर्ष औसत

स्रोत: \*सभी भारत- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

\*\*राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय, 68<sup>वां</sup> राउंड, 2011-12

\*\*\*राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 68<sup>वां</sup> राउंड, 2011-12

#जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

##जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार

∞ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### 3. अवसंरचना स्थिति

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
घर के अंदर नल के पानी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत (बनाये गए स्रोतों से)	80.93	66.08	84.14
बिजली के उपयोग के साथ घरों का %	98.89	98.34	92.68
घर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का %	92.58	85.61	72.57
गंदे पानी के माध्यमों का ड्रेनेज से जुड़े परिवारों का प्रतिशत	89.47	90.9	81.77
सीवरेज प्रणाली का प्रकार*	भूमिगत सीवरेज प्रणाली		
ठोस अपशिष्ट प्रणाली का प्रकार*	द्वार से द्वार		
कम्प्यूटर/लैपटॉप का इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	69.12	10.55	8.27
कम्प्यूटर/लैपटॉप का बिना इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	10.55	11.64	10.40
मोबाइल फोन के उपयोग के साथ घरों का %	65.30	63.17	64.33
आवास का स्वामित्व पैटर्न (%)			
स्वामित्व	69.12	78.30	69.16
किराए पर	27.76	18.63	27.55
भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों का %	30.90	24.20	32.94
<b>संकेतक</b>	<b>शहर (नगर निगम)</b>		
प्रति 1,00,000 लोगों पर अस्पतालों की संख्या*	0.06		
प्रति 1,00,000 लोगों पर स्कूलों की संख्या*			
प्राथमिक	15		
माध्यमिक	3		
द्वितीयक	10		
महाविद्यालय	5		

स्रोत: मकान, घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

\*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

#### 4. राजनीतिक प्रोफाइल: नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचा

##### शासन की वास्तुकला

*चुने गए एवं कार्यकारी निकायों की संरचना।  
पदानुक्रम के संकेत दें।*

लुधियाना में नागरिक प्रशासन मुख्य रूप से लुधियाना नगर निगम (एमसीएल) के प्रबंधन एवं नियंत्रण में है। लुधियाना नगर निगम (एमसीएल) के अलावा अन्य संस्थान शहर के विकास के समग्र प्रबंधन में शामिल हैं। लुधियाना नगर निगम चार जोन अर्थात् जोन ए, जोन बी, जोन सी एवं जोन डी में विभाजित है और प्रत्येक जोन लुधियाना नगर निगम के आयुक्त के संपूर्ण नियंत्रण के साथ जोनल आयुक्त द्वारा संचालित की जाती है। विभिन्न शाखाओं में सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्यों के नियंत्रण एवं निगरानी हेतु आयुक्त की सहायता करने के लिए संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्तों को भी जोड़ा गया है। निर्वाचित विंग में वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में लुधियाना नगर निगम के नागरिकों द्वारा निर्वाचित पार्षद होते हैं। महापौर को पार्षदों द्वारा निर्वाचित वरिष्ठ उप महापौर एवं उप महापौर सहायता करते हैं। इन तीनों महापौरों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। लुधियाना नगर निगम (एमसीएल) की वित्त और अनुबंध समिति एवं हाउस टैक्स आकलन समिति हैं जो दो वैधानिक समितियां एवं वार्ड समितियां हैं जिनमें संबंधित वार्ड के निर्वाचित पार्षद होते हैं एवं एक अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती है।

बेतरतीब शहरी गंदगी पर नियंत्रण करने, नगर निगम सीमा के साथ बाहरी उप नगरीय क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर विकास (आवास विकास योजनाएं) एवं प्रतिस्पर्धी गतिविधि केन्द्रों के विकास द्वारा एक भीड़भाड़ वाले शहर में गतिविधियों के योजनागत विकेन्द्रीकरण को उपलब्ध कराने और श्रेणीबद्ध सड़क नेटवर्क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करके योजनागत विकास को प्रदान करने के लिए लुधियाना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जिम्मेदार है।

योजना, विकास एवं प्रबंधन में सुधार और शहरी केन्द्रों की आपूर्ति क्षमता के द्वारा लुधियाना में व्यापक, एकीकृत और व्यवस्थित विकास के लिए ग्रेटर लुधियाना एरीआ विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है। मुख्य मंत्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

शहरी स्थानीय निकायों की जल आपूर्ति एवं सीवरेज के विभिन्न कार्यों की योजना, डिजाइन एवं निष्पादन के लिए पंजाब वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड (पीडब्ल्यूएसएसबी) जिम्मेदार है।

पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) शहर में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यरत है। पीयूडीए पंजाब राज्य में संतुलित शहरी विकास के लिए जुलाई, 1995 में स्थापित एक शीर्ष संस्था है। पीयूडीए

	<p>अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नवीनतम राज्य एवं टाउन प्लानिंग मानदंडों को शामिल करके योजनागत आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक रिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना उनकी मंजूरी लिए कॉलोनी डेवलप करने वाले प्राइवेट डेवलपर के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति है।</p> <p>पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लुधियाना (पीपीसीबी) औद्योगिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और इसके साथ-साथ एमसीएल का एमएसडब्ल्यू पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1996 के तहत वायु प्रदूषण की जांच करता है।</p> <p>नगरीय योजना से संबंधित गतिविधियां शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं। विभाग मास्टर प्लान तैयार करने, मास्टर प्लान को अपडेट एवं समीक्षा करने, विकास योजना को तैयार करने, टाउन प्रोटेक्शन स्कीम, वीएएमबीएवाई, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, कोहिमा के लिए स्लम इम्प्रूवमेन्ट एवं अपग्रेडेशन परियोजना जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नागालैण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीएसबी) हवा और पानी की गुणवत्ता पर जोर देने के साथ राज्य स्तर पर पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एवं पर्यावरण विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए राज्य स्तर पर समान प्रकार का कार्य करता है।</p>
निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.	लागू नहीं
<p><u>निर्वाचन विवरण*</u></p> <p><i>चुनाव चक्र, पिछला चुनाव, नाम, जहां प्रासंगिक हो पार्टी की संबद्धता, मुख्यमंत्री, आयुक्त एवं महापौर के लिए कार्यालय ग्रहण करने की तारीख।</i></p>	<p>शिरोमणि अकाली दल से श्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्य मंत्री हैं। वह 15 मार्च 2012 को निर्वाचित किए गए थे। आयुक्त श्री जी.के. सिंह हैं। परिषद का नेतृत्व शिरोमणि अकाली दल के महापौर श्री हरचरन सिंह गोहलवारीया द्वारा किया जाता है, जो सितम्बर 2012 में निर्वाचित हुई। नगर निगम के चुनाव वर्ष 2012 में आयोजित किए गए।</p>

स्रोत: \*संबंधित यूएलबी वेबसाइट और मीडिया सर्च

## 5. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यनिष्पादन

### क्रेडिट और कर

शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग (नवम्बर 2012 तक)*	बीबीबी-
संपत्ति कर#	कवरेज (%): 57.1%

	संग्रह क्षमता (%): 68 राशि (रु.): 61.33 करोड़
--	--

स्रोत: \*www.jnnurm.nic.in

\*रिफॉर्म मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

### शहरी स्थानीय निकायों में ई-शासन एवं कम्प्यूटरीकरण

सुधार	स्थिति (कार्यान्वित, प्रगति में और किसी भी टिप्पणी में)
संपत्ति कर*	कार्यान्वित
लेखांकन*	कार्यान्वित
जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं*	कार्यान्वित
जन्म और मृत्यु पंजीकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम*	कार्यान्वित
नागरिक शिकायत निगरानी*	कार्यान्वित
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली*	कार्यान्वित
निर्माण योजना अनुमोदन*	कार्यान्वित
ई-प्रापण*	कार्यान्वित
क्या नागरिक अपने बिल एवं करों का भुगतान सिटिजन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) पर कर सकते हैं?#	केवल सीएफसी पर
क्या शहरी स्थानीय निकायों पर भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा है#	नहीं
शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किया जाने वाला ई-मेल सॉफ्टवेयर क्या है#	एनआईसी
क्या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)/वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से एक दूसरे से	नहीं

जुड़े हुए हैं#	
क्या आप स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) का उपयोग करते हैं?#	नहीं
क्या शहरी स्थानीय निकाय की स्वयं की वेबसाइट है#	हाँ: mcludhiana.gov.in
74 <sup>वें</sup> सीएए का कार्यान्वयन#	2 कार्यों को अभी ट्रांसफर किया जाना शेष है। वे हैं शहरी गरीबी उपशमन; कमजोर वर्गों के समाज के हितों की रक्षा

नोट: \*शहरी स्थानीय निकाय में ई-गवर्नेंस के मॉड्यूल कार्यान्वित

स्रोत: \*सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

### मान्यता

राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानों, पुरस्कारों, पायलटों, क्षैतिज नेटवर्कों की सूची।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एसीसीसीआरएन परियोजनाएं</li> <li>• इंडिया टुडे बेस्ट सिटी अवार्ड्स: बेस्ट इमर्जिंग इन हाउसिंग</li> <li>• भारत के शीर्ष 20 उदीयमान शहरों में स्मार्ट शहर परिषद</li> </ul>
---	--

## 6. वित्तीय एवं स्वास्थ्य

### वित्तीय

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के साथ घरों का %*	64.81	68.97	67.77

वित्तीय स्थिति#		
नगर निगम के आय और व्यय का विवरण (लाख रु. में)	आय	व्यय
2009-10	41364.01	35803.05
2010-11	55512.15	56818.06



2011-12	58078.48	59742.85
नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित बजट का प्रतिशत@		

स्रोत: \*मकान, घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

@जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट

## पर्यावरण

स्वच्छ भारत रैंकिंग*	381
उपलब्ध शहरों के लिए व्यापक पर्यावरण आकलन#	81.66

स्रोत: \*प्रेस सूचना ब्यूरो, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2015

#केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009

## 7. क्षमता: टैक रिकार्ड और पहल

जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं	स्थिति या टिप्पणी
बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	बीएसयूपी योजना के तहत, आवास के लिए कुल 2 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं जिसमें से 1 परियोजना रद्द कर दी गई है। आवास की 1 परियोजना प्रगति में है। परियोजना की कुल लागत रु. 50.09 करोड़ थी। 82 प्रतिशत घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी	यूआईजी: कुल 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, 1 परियोजना प्रगति में है तथा 1 परियोजना शुरू की गई है।
परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	33924.00

परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	कुल लागत (लाख रु. में)	कुल स्वीकृत परियोजनाओं में क्षेत्र की हिस्सेदारी
	सीवरेज	1	24139	71.2
	एसडब्ल्यूएम	3	9785	28.8
केन्द्र द्वारा जारी सहायता का हिस्सा (प्रतिशत)	47.95			
पूरा किए हुए कार्य का प्रतिशत (वास्तविक प्रगति)	26			
उपयोग किया गया वित्त (प्रतिशत)	49.98			

स्रोत: www.jnnurm.nic.in (नवम्बर, 2015 तक पहुंच)

शहरी विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ एकीकरण	स्थिति, टिप्पणी
विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)	
अमृत	शहर अमृत मिशन के तहत शामिल है
जेएनएनयूआरएम	शहर जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक तहत कवर था।
एनयूआईएस	शहर एनयूआईएस के तहत कवर है
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	

स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार